



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 39] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 27, 1980 (आश्विन 5, 1902)
No. 39] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 27, 1980 (ASVINA 5, 1902)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

विषय-सूची

पृष्ठ

पृष्ठ

भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	557	किए गए साधारण नियम (जिसमें साधारण प्रकार के प्रादेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)	2059
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	1225	भाग II—खण्ड 3—उप खण्ड (ii)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए प्रादेश और अधिसूचनाएं	3359
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	17	भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और प्रादेश	3336 to 34
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	1059	भाग III—खण्ड 1—महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	10375
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	—	भाग III—खण्ड 2—एकलव्य कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस	481
भाग II—खण्ड 2—विधेयक और विधेयक संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्टें	—	भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	63
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी	—	भाग III—खण्ड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विधिक अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	3337
		भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिस	165

*पृष्ठ संख्या प्राप्त नहीं हुई।

CONTENTS

	PAGE		PAGE
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	557	(other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	*
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	225	PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii).—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	*
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	17	PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence ..	*
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	1059	PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	10375
PART II—SECTION 1.—Act, Ordinances and Regulations.	—	PART III—SECTION 2.—Notification and Notices issued by the Patent Office, Calcutta ..	481
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committee on Bills	—	PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	63
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (i).—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India		PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	3337
		PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies ..	165

भाग I—खण्ड 1
PART I—SECTION 1



(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई
विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

कम्पनी कार्य विभाग

(कम्पनी विधि बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 6 सितम्बर 1980

आदेश

सं० 27(26)80-सी० एल० II—कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209क की उपधारा (1) के खण्ड (II) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त धारा 209क के उद्देश्यों के लिए, भारत सरकार, कम्पनी कार्य विभाग के निम्नलिखित अधिकारियों को प्राधिकृत करती है:—

1. श्री अमलेन्दु दास, उप निदेशक, निरीक्षण, कलकत्ता
2. श्री डी० के० विप्रवास, संयुक्त निदेशक, निरीक्षण, मद्रास

एस० बलरामन, अवसर सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 1 अगस्त 1980

सं० 17014/17/80-टी०सी०—हम मंत्रालय के सकल संख्या 3/4/80-सी० एल० सी०, दिनांक 10 मई, 1980 के क्रम से भारत सरकार ने अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों से संबंधित उच्च शक्ति प्राप्त समिति का कार्यकाल सरकार को अपनी रिपोर्ट 30 अगस्त, 1981 तक प्रस्तुत करने के निमित्त बढ़ा दिया है।

माताप्रसाद श्रीवास्तव, निदेशक

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 8 सितम्बर 1980

सं० 2(9)/80-एस०आर०-2—बाडिया इंस्टीट्यूट आफ हिमालयन जियोलोजी (बाडिया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान) (जो कि सोसाइटी ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट (1960 का 21वां) के अधीन एक पंजीकृत सोसाइटी है) के अस्तित्वों के शापन के अंतर्निहित 19(1) के अनुसरण में भारत सरकार 5-9-1980 से तीन वर्ष की अवधि के लिए सेंटर फार अर्थ साइंसिज स्टडीज, त्रिवेंद्रम के निदेशक श्री सी० करुणाकर को सहर्ष बाडिया इंस्टीट्यूट आफ हिमालयन जियोलोजी का अध्यक्ष नियुक्त करती है।

एस० एन० कुरेशी, निदेशक

सिंचाई मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 4 सितम्बर 1980

संकल्प

सं० 22/7/80-परि० एक—गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्यों के बीच अन्तर्राष्ट्रिय नदी नर्मदा और उसकी नदी आदी से

संबंधित जल-विवाद, अन्तर्राष्ट्रियक जल-विवाद अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अक्टूबर, 1969 में स्थापित नर्मदा जल-विवाद व्याधिधिकरण को निर्णय देने के लिए सौंपा गया था। व्याधिधिकरण ने अपनी अगली और अन्तिम रिपोर्ट भारत सरकार को दिसम्बर, 1979 में प्रस्तुत कर दी थी। जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत अपेक्षित है, भारत सरकार ने व्याधिधिकरण का निर्णय राजपत्र में 12 दिसम्बर, 1979 को प्रकाशित कर दिया था जिससे व्याधिधिकरण का निर्णय अन्तिम और विवाद के पक्षों पर आबद्ध हो गया। व्याधिधिकरण ने अपने अन्तिम आवेदन में, अन्य बातों के साथ-साथ, एक अन्तर्राष्ट्रियक प्रशासनिक प्राधिकरण की जिसका नाम नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण होगा, स्थापना करने का निर्देश दिया था। उक्त प्राधिकरण की स्थापना का उद्देश्य व्याधिधिकरण के निर्णयों और निर्देशों का पालन और त्रियान्वयन कराना है। व्याधिधिकरण ने इनके अलावा एक पुरोक्षण समिति की स्थापना करने का भी निर्देश दिया है जो किसी भी पक्ष राज्य द्वारा अनुरोध किए जाने पर प्राधिकरण के किसी निर्णय का पुरोक्षण कर सकती है। यह देखते हुए कि सरदार सरोवर परियोजना के यूनिट-एक के बाँध और आनुषंगिक निर्माण-कार्यों के संबंध में चारों पक्ष राज्यों की वित्तीय जिम्मेदारी है और उनमें से तीन राज्यों, नामशः गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सरदार सरोवर परियोजना के यूनिट-तीन और विद्युत काम्पलेक्स के संबंध में जिम्मेदारी है, व्याधिधिकरण ने यह भी बांछनीय और आवश्यक समझा है कि परियोजना के यूनिट-एक और तीन के कुशलतापूर्वक, मितव्ययतापूर्ण और शीघ्र त्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक निर्माण सलाहकार समिति गठित की जानी चाहिए।

नर्मदा जल-विवाद व्याधिधिकरण के उक्त निर्णय के अनुसरण में, एतद्वारा सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति निम्न प्रकार से गठित की जाती है:—

2 सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे:—

- (i) सचिव, भारत सरकार (सिंचाई के प्रधानी) अध्यक्ष
- (ii) अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग अथवा उनके बैठक सदस्य में भाग न ले सकने की स्थिति में उनके प्रतिनिधि के रूप में केन्द्रीय जल आयोग का कोई एक सदस्य
- (iii) अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण अथवा उनके बैठक में भाग न ले सकने की स्थिति में उनके प्रतिनिधि के रूप में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण का कोई एक सदस्य
- (iv) अध्यक्ष, नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण अथवा उनके बैठक में भाग न ले सकने की स्थिति में उनके प्रतिनिधि के रूप में प्राधिकरण का कोई एक स्तंत्र सदस्य
- (v) सिंचाई विभाग में संयुक्त सचिव (विशेष सलाहकार), सदस्य कार)

- (vi) मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान की सदस्य सरकारों के वित्त विभागों के प्रभारी सचिव
- (vii) गुजरात और राजस्थान की सरकारों के सिंचाई : सदस्य विभागों के प्रभारी सचिव
- (viii) मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के विद्युत सदस्य विभागों के प्रभारी सचिव
- (ix) मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के राजस्व सदस्य विभाग अथवा भूमि अधिग्रहण से संबंधित किसी अन्य विभाग के प्रभारी सचिव
- (x) गुजरात के महाप्रबंधक अथवा मुख्य इंजीनियर जो इस परियोजना के प्रभारी हों तथा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र राजस्थान के इस परियोजना से संबंधित मुख्य इंजीनियर
- (xi) मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य विजली सदस्य बोर्डों के अध्यक्ष
- (xii) वित्तीय सलाहकार, सरदार सरोवर परियोजना सदस्य
- (xiii) सचिव (जिसकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की सचिव जानी है)

अध्यक्ष सलाहकार समिति की किसी बैठक में किसी अन्य व्यक्ति को भी भाग लेने के लिए आमंत्रित कर सकता है, यदि वह यह समझे कि समिति द्वारा अपने कार्यों को सुचारु रूप से निभाने के लिए ऐसा करना आवश्यक है।

3. सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति के कार्य निम्नलिखित होंगे:—

- (i) उपर्युक्त पैरा 1 में उल्लिखित निर्माण कार्यों के लिए सैवार किए गए परियोजना-अनुमानों की संश्लेषण करना, उनमें आवश्यक संशोधन करने की सलाह देना और संबंधित सरकारों को अनुमानों को प्रशासनिक स्वीकृति देने के लिए सिफारिश करना;
- (ii) तकनीकी पहलुओं और डिजाइनों के बारे में किसी एक राज्य द्वारा भेजे गए सभी प्रस्तावों की जांच करना और सिफारिशें करना तथा जहाँ आवश्यक हो वहाँ विशेषज्ञों की सलाह लेना;
- (iii) उपलब्ध धनराशि, परियोजना की अर्थव्यवस्था और परियोजना से शीघ्र लाभ प्राप्त करने की वांछनीयता को ध्यान में रखते हुए परियोजना के विभिन्न भागों के समन्वित ढंग से निर्माण के कार्यक्रम की जांच करना और सिफारिशें करना;
- (iv) स्वीकृत कार्यक्रम के अन्तर्गत धरसों के निर्माण और अन्य प्रयोजनों के लिए धन की आवश्यकता की जांच करना और आवश्यक सिफारिशें करना;
- (v) परियोजना के सुचारु रूप से प्रियोजना के लिए परियोजना के निर्माण में सगे अधिकारियों को आवश्यकतानुसार तकनीकी और वित्तीय दोनों प्रकार की शक्तियों के प्रत्यायोजन की समय-समय पर जांच करना और सिफारिशें करना;

- (vi) विभिन्न किस्मों के वर्कस की विनिष्टियों की जांच करना और और जहाँ आवश्यक हों वहाँ विनिष्टियों की मरफटि कराना;
- (vii) उन सभी उप-अनुमानों और संविदाओं की जांच करना और सिफारिश करना जिनकी लागत उस राशि से अधिक हो, जिसकी स्वीकृति देने का अधिकार महाप्रबंधक/मुख्य इंजीनियरों को प्राप्त है;
- (viii) निर्माण-कार्यों और व्यवधानों के बारे में महाप्रबंधक/मुख्य इंजीनियरों से प्राप्त प्रगति रिपोर्टों की संश्लेषण करना और जहाँ आवश्यक हो, वहाँ कार्य के शीघ्र निष्पादन के उपायों की सिफारिश करना।

4. निर्माण सलाहकार समिति की सिफारिशों समिति द्वारा संबंधित राज्यों के पास भेजी जाएंगी और उनकी प्रतियां पुनरीक्षण समिति और नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण को सूचनायें भेजी जाएंगी।

5. निर्माण सलाहकार समिति की सिफारिशें आमतौर पर संबंधित राज्य सरकारों द्वारा स्वीकार कर ली जाएंगी। मतभेद होने की दशा में, मामला पुनरीक्षण समिति के पास भेजा जाएगा और पुनरीक्षण समिति का निर्णय अंतिम और सभी संबंधित राज्यों पर आबद्धकर होगा।

सरदार सरोवर धांध और सम्बंध वर्कस विद्युत-गृह और विद्युत उत्पादन मशीनरी (यूनिट-तीन) और (यूनिट-एक), मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात को प्रत्येक मामले में अगले एब-स्टेशन तक विद्युत देने वाली पारेषण लाइनों के निर्माण से संबंधित सभी मामलों में नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण केवल वे कार्य करेगी जिन्हें विशिष्ट रूप से निर्माण सलाहकार समिति के जिम्मे नहीं डाला गया है।

6. निर्माण सलाहकार समिति सरदार सरोवर परियोजना के यूनिट-एक और तीन के निर्माण कार्य के पूरा हो जाने के तीन वर्ष बाद विद्युतित हो जाएगी। एक-एक और तीन का निर्माणोत्तर प्रबंध गुजरात द्वारा नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की में किया जाएगा।

7. निर्माण सलाहकार समिति का मुख्य कार्यालय गांधीनगर, गुजरात में होगा।

8. निर्माण सलाहकार समिति अपने कार्य के संचालन के लिए प्रतिष्ठा और शक्तियों के प्रत्यायोजन के बारे में नियम बनाएगी।

9. निर्माण सलाहकार समिति पर होने वाला व्यय चारों राज्यों अर्थात् मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान द्वारा बराबर-बराबर वहन किया जाएगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सभी राज्य सरकारों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति, सचिवालय और योजना आयोग के पास भेजा जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए और राज्य सरकारों से अंतर्दोष किया जाए कि वे इस संकल्प को आम जानकारी के लिए राज्यों के राजपत्रों में प्रकाशित करें।

सी० सी० पटेल, सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY
AFFAIRS

DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS

New Delhi-1, the 6th September 1980.

ORDER

No. 47/26/80-CL.II.—In pursuance of clause (ii) of sub-section (1) of Section 209-A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby authorises the following Officers of the Government of India in the Department of Company Affairs for the purposes of the said Section 209A :—

1. Shri Amalendu Das,
Deputy Director Inspection,
Calcutta.
2. Shri D. K. Biswas,
Jt. Director Inspection,
Madras.

S. BALARAMAN, Under Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-110001, the 1st August 1980

No. 17014/17/80-1D.—In continuation of this Ministry's Resolution No. 3/4/80-CHC, dated the 10th May, 1980, the Government of India has extended the tenure of the High Power Panel on Minorities, Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Weaker Sections for submission of its Report to Government by the 30th August, 1981.

M. P. SRIVASTAVA, Director

DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

New Delhi-110029, the 8th September 1980

No. 2(9)/80-SR.II.—In pursuance of Article 19(1) of the Memorandum of Association of the Wadia Institute of Himalayan Geology [A registered society under the Societies Registration Act (Act XXI, of 1860)], the Government of India is pleased to appoint Shri C. Karunakaran, Director, Centre for Earth Sciences Studies, Trivandrum, as President of the Wadia Institute of Himalayan Geology, with effect from 5-9-1980 for a period of three years.

M. N. QURESHY, Director

MINISTRY OF IRRIGATION

New Delhi, the 4th September 1980

RESOLUTION

No. 22/7/80-P-I.—The water dispute regarding the inter-State river Narmada and the river valley thereof, between the States of Gujarat, Madhya Pradesh, Maharashtra and Rajasthan was referred for adjudication to the Narmada Water Disputes Tribunal constituted by the Government of India in October, 1969 under the Inter-State Water Disputes Act, 1956. The Tribunal submitted its further and final report to the Government of India in December 1979. As required under Section 6 of the Act, the Government of India published the decision of the Tribunal in the Official Gazette on 12th December, 1979, whereupon the decision became final and binding on the parties to the dispute. In its final order, the Tribunal has, *inter-alia*, directed setting up of an Inter-State Administrative Authority to be called Narmada Control Authority for the purpose of securing compliance with and implementation of the decisions and directions of the Tribunal. The Tribunal has further directed the setting up of a Review Committee which on the application of any party State may review any decision of the Authority. While observing that the four party States have financial commitments in respect of Unit-I-Dam and Appurtenant Works of the Sardar Sarovar Project and three of them, namely, Gujarat, Maharashtra and Madhya Pradesh have such commitment in respect of Unit III Power Complex of the Sardar Sarovar Project, the Tribunal has in addition considered it desirable and necessary that a Construction Advisory Committee should be constituted for ensuring efficient, economical and early execution of units I and III of the project.

In pursuance of the above decision of the Narmada Water Disputes Tribunal, the Sardar Sarovar Construction Advisory Committee is hereby constituted, as under :—

—~~2.~~ The Sardar Sarovar Construction Advisory Committee will consist of the following :—

- (i) ~~The Secretary to the Government of India, in charge of Irrigation.~~ Chairman
- (ii) Chairman, Central Water Commission (CWC) or a Member of the CWC representing him in case the Chairman is unable to attend the meeting.
- (iii) Chairman, Central Electricity Authority (CEA) or a Member of the CEA representing him in case the Chairman is unable to attend a meeting. Member
- (iv) Chairman, Narmada Control Authority (NCA) or its Independent Member representing Chairman in case the Chairman is unable to attend a meeting. Member
- (1) Joint Secretary (Financial Adviser) in the Ministry of Irrigation. Member
- (vi) Secretaries in charge of Finance Department of Governments of Madhya Pradesh, Gujarat, Maharashtra and Rajasthan. Members
- (vii) Secretaries in charge of Irrigation Department of Governments of Gujarat and Rajasthan. Members
- (viii) Secretaries in charge of Power Department of Madhya Pradesh, Maharashtra and Gujarat. Members
- (ix) Secretaries in charge of Revenue Department or any other Department, concerned with land acquisition of Madhya Pradesh, Maharashtra and Gujarat. Members
- (x) General Manager or Chief Engineers of Gujarat in charge of the project and Chief Engineers of Madhya Pradesh, Maharashtra and Rajasthan concerned with the project. Members
- (xi) Chairman, State Electricity Board of Madhya Pradesh, Maharashtra and Gujarat. Members
- (xii) Financial Adviser, Sardar Sarovar Project. Member
- (xiii) Secretary (to be appointed by the Government of India). Secretary

The Chairman may invite any other person to attend any meeting of the Advisory Committee, should be consider it necessary for the proper discharge by the Committee of its functions.

3. The Sardar Sarovar Construction Advisory Committee shall :—

- (i) scrutinise the project estimates prepared for works mention in paragraph 1 above, advise necessary modifications and recommend the estimates for the administrative approval of the concerned Governments;
- (ii) examine and make recommendation on all proposal pertaining to technical features and designs as may be referred to it by any of the party States and where necessary consult experts for the purpose;
- (iii) examine and make recommendation on the programme of construction of different parts of the project in a co-ordinated manner, keeping in view the funds available, the economics of the project and the desirability of obtaining quick results;
- (iv) examine the requirements of funds for the construction of works and other purposes according to the approved programme and make necessary recommendation.

- (v) examine and recommend, from time to time, the delegation of such powers, both technical and financial, as it may deem necessary for the efficient execution of the project, to the officers engaged in the execution of the works on the project,
- (vi) examine and, where necessary, recommend specifications for various classes of work;
- (vii) examine and make recommendation on all sub-estimates and contracts, the cost of which exceeds the powers of sanction of the General Manager/Chief Engineers;
- (viii) review progress reports, both for works and expenditure from the General Manager/Chief Engineers and recommend, where necessary, steps to be taken to expedite the work.

4. The recommendations of the Construction Advisory Committee shall be conveyed to the Governments concerned by the Committee and copies sent to the Review Committee and Narmada Control Authority for information.

5. The recommendations of the Construction Advisory Committee shall normally be accepted by the State Governments concerned. In the event of any disagreement, the matter shall be referred to the Review Committee and the decision of the Review Committee shall be final and binding on all the concerned States.

In all matters relating to the construction of the Sardar Sarovar Dam and appurtenant works (Unit I), Power House and generating machinery (Unit III) and Transmission lines to feed power to Madhya Pradesh, Maharashtra and Gujarat

upto the next sub-station in each case, the Narmada Control Authority will carry out only such functions as do not specifically devolve upon the Construction Advisory Committee.

6. The Construction Advisory Committee will be subject to dissolution after three years of the completion of constructions of Units I and III of the Sardar Sarovar Project. The post construction management of Units I and III will be by Gujarat under the supervision of the Narmada Control Authority.

7. The headquarters of the Construction Advisory Committee shall be at Gandhinagar in Gujarat.

8. The Construction Advisory Committee will frame rules regarding procedure and delegation of power for the purpose of carrying out its business.

9. The expenditure of the Construction Advisory Committee will be borne by the four States of Madhya Pradesh, Gujarat, Maharashtra and Rajasthan equally.

ORDER

ORDERED that this Resolution be communicated to all the State Governments, Ministries/Departments of the Government of India, the Comptroller and Auditor General of India, Prime Minister's Office, President's Secretariat and Planning Commission.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India and that the State Governments be requested to publish it in the State Gazette for general information.

S. C. PATEL, Secy